

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 157/2019

गोपाल प्रसाद शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.02.2019

आदेश की दिनांक : 30.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खाण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष  
शुचि शर्मा, सदस्य

### आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 18.05.2017 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से समस्त सेवा लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी आदेश दिनांक 30.07.1987 के द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्त हुआ था और उसकी सेवायें आदेश दिनांक 28.05.1991 के द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को नियमित किया गया और अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 01.08.1996 से प्रथम

चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया और 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी का द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.08.2005 से देय था, परंतु आदेश दिनांक 16.09.2011 के द्वारा दिनांक 01.08.2014 से दिया गया। उनका कथन है कि उसकी नियुक्ति पर दिनांक 28.09.1992 से मानते हुये द्वितीय चयनित वेतनमान दिया गया। जबकि आदेश दिनांक 28.07.1990 के द्वारा दिनांक 01.08.1987 से स्थायी किया गया है। इसी प्रकार समान मामले में अन्य कार्मिकों को माननीय न्यायालय द्वारा चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14739/2016 गोपाल प्रसाद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.10.2016 के द्वारा आदेश पारित करते हुये अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश और प्रत्यर्थी विभाग को नियमानुसार निस्तारण करने हेतु आदेश दिया। अपीलार्थी ने उक्त पालना में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और आदेश दिनांक 18.05.2017 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 18.05.2017 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से समस्त सेवा लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति 30.07.1987 के द्वारा अस्थायी तौर पर तदर्थ नियुक्ति प्रदान की गई थी और विभाग के आदेश दिनांक 20.08.2010 की पालना में अपीलार्थी को पूर्व में प्रदान किया गया प्रथम चयनित वेतनमान को रिव्यू कर संशोधित नहीं किया गया तथा आगामी देय चयनित वेतनमान को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसरण में नियमित नियुक्ति तिथी से स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी के स्क्रीनिंग आदेश दिनांक 18.07.1991 को जारी किये गये और उक्त आधार पर ही 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 18.07.2009 से स्वीकृत किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को अस्थाई तौर पर तदर्थ नियुक्ति आदेश दिनांक 30.07.1987 के द्वारा प्रदान की गई। जिसमें यह अंकित था कि उनकी अस्थाई नियुक्ति अध्यापक पद पर चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, तब तक के लिए वेतन श्रृंखला 880-15-1000-20-1200-25-1400-50-1640-40-1680 में की जाती है। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जो नियुक्ति दिनांक 30.07.1987 को हुई थी, वह नियमित नियुक्ति नहीं थी, बल्कि ad-hoc के रूप में हुई थी। यह भी स्पष्ट है कि बाद में अपीलार्थी की सेवाएं आदेश दिनांक 28.09.1991 के द्वारा जिला स्थाई समिति के निर्णय के अनुसार नियमित की गई थी। इस बिन्दू पर कोई आपत्ति नहीं है कि राज्य सरकार के अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की गई थी और स्क्रीनिंग के पश्चात जिला स्थापना समिति के आदेश से अपीलार्थी की सेवाएं नियमित की गई थी।

माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two

decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

अतः बिन्दू संख्या-1 व 4 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवा नियमित मानी जाएगी। यह भी माना है कि वरिष्ठता या अन्य लाभ के संबंध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारिख नहीं हो सकती।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जो सेवाएं 28.09.1991 को स्क्रीनिंग के बाद नियमित की गई, उसकी पूर्व की सेवाओं को अपीलार्थी वरिष्ठता व अन्य लाभ के लिए अपनी सेवा अवधि में नहीं जुड़वा सकता है। अतः अपीलार्थी को जो नियमितिकरण की दिनांक 28.09.1991 से नियमित मानते हुए उसी दिनांक से वरिष्ठता दी गई। उसमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)  
अध्यक्ष